संपादकीय जागरण

रविवार, 22 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 10 वि. 2075

जिंदगी की वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है

बेलगाम अराजकता

एक ऐसे समय जब सड़क से लेकर संसद तक भीड़ की हिंसा के मामले चर्चा और चिंता का विषय बने हुए हैं तब राजस्थान के अलवर जिले में गो-तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या यही बताती है कि ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं। यह वही अलवर जिला है जहां करीब एक साल पहले एक अन्य व्यक्ति को इसी तरह गो-तस्कर मानकर मार दिया गया था। इसका मतलब है कि गोरक्षा के नाम पर अराजकता का सहारा लेने वाले तत्व बेलगाम बने हुए हैं। चिंताजनक यह है कि राजस्थान में तथाकथित गो-रक्षकों की हिंसा के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। अगर कानून एवं व्यवस्था को नीचा दिखाने और सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली ऐसी घटनाओं पर सख्ती नहीं बरती गई तो वे देश की बदनामी का कारण ही बनेंगी। राजस्थान सरकार ने अलवर की घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात अवश्य कही है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि उसने जो कहा है उस पर अमल करे। यह भी जरूरी है कि वह उन अराजक तत्वों को हर संभव तरीके से नियंत्रित करे जो गो-रक्षक का चोला धारण कर हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। यह काम अन्य राज्य सरकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर करना होगा, क्योंकि कथित गो-रक्षकों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है।

आखिर ये कैसे गो-रक्षक हैं जो किसी की परवाह करते नहीं दिख रहे हैं? ध्यान रहे कि चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा रोकने के लिए जो दिशानिर्देश जारी किए थे वे मूलतः उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिए थे जिसमें गो-रक्षा के नाम पर हो रहे हिंसक व्यवहार को कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया था। हालांकि केंद्र सरकार और यहां तक कि खुद गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि हिंसा का सहारा लेने वाले फर्जी गो-रक्षक हैं और उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन कोई नहीं जानता कि राज्य सरकारें पर्याप्त सख्ती क्यों नहीं बरत रहीं? यह समझना भी कठिन है कि इन उत्पाती तत्वों को कहां से बल मिल रहा है? निःसंदेह भीड़ की हिंसा के कई ऐसे भी मामले रहे हैं जिनके केंद्र में गाय नहीं थी, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि कथित गो-रक्षकों की अराजकता मोदी सरकार की छवि पर बहुत भारी पड़ रही है। चूंकि गाय के नाम पर हो रही हिंसा के कारण मोदी सरकार की राष्ट्रीय से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हो रही है इसलिए उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सक्रियता बढ़ाए। माना कि कानून एवं व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है और केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश ही दे सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। आज के युग में भीड़ की हिंसा को लेकर यह तर्क नहीं चल सकता कि पहले भी ऐसे मामले होते रहे हैं, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरता दिख रहा है।

पिछली करतूतें

पिछली राज्य सरकार में परिषदीय विद्यालयों में जमकर फर्जी नियुक्तियां हुईं। अब इसकी शिकायतें आने लगी हैं। अब योगी सरकार सभी जिलों में परिषदीय शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों की जांच कराने जा रही है। जिलाधिकारियों को वर्ष 2010 के बाद की गईं नियुक्तियों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। जिलों में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। वर्ष 2010 के बाद 1.15 लाख प्राथमिक शिक्षकों की हुईं कई भर्तियां जांच के दायरे में आएंगी। फर्जी नियुक्तियों की जांच तो हो रही है, जो इसके दायरे में आएंगे उनकी नौकरी भी जाएगी लेकिन, इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। देखने में आ रहा है कि भर्तियों में छोटी-छोटी गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थी अदालत का रुख कर रहे हैं लेकिन, ये भर्तियां इतनी फूलप्रूफ कैसे रहीं कि पात्र अभ्यर्थियों को इसमें गड़बड़ी का पता नहीं लग पाया और अब पता लगने के बाद वे चुप्पी क्यों साधे हैं। दूसरा यह कि फर्जी नियुक्तियों के मामले में जिन लोगों ने अपनी जेबें भरीं या जिनकी शह पर ऐसे कारनामों को अंजाम दिया गया, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाएगी। मुश्किल यहीं है।

> सरकार ने जो मुहिम शुरू की है, उम्मीद है वह मुकाम तक पहुंचेगी और बिना भेदभाव के सभी दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई भी होगी

भ्रष्टाचार आमतौर से ऊपर से नीचे की ओर चलता है, जबकि उसकी जांच नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसी तरह कार्रवाई नीचे से शुरू तो होती है लेकिन, ऊपर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। भ्रष्टाचार और उसकी जांच तथा कार्रवाई की यह विपरीत प्रवृत्ति जब तक बनी रहेगी, समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार की बड़ी मछलियों को जाल के भीतर लाया जाए, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हों। बहरहाल, सरकार ने जो मुहिम शुरू की है, उम्मीद है वह मुकाम तक पहुंचेगी और बिना भेदभाव के सभी दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई भी होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अफवाहों से निपटने के लिए वाट्सएप का डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम कारगर साबित होगा?

आज का सवाल
संसद में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगना क्या संसदीय गरिमा के अनुरूप था?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

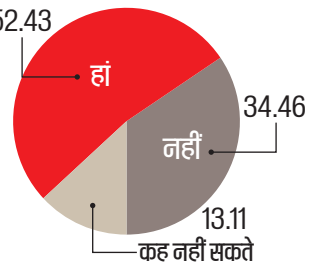

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अपनी ही चाल में फंसा विपक्ष

संजय गुप्त

प्रधानमंत्री ने बैंकों के फंसे कर्जे पर भी विपक्षी दलों को आईना दिखाते हुए जिस तरह अनुत्तरित किया उससे यही लगा कि अविश्वास प्रस्ताव उनके और खासकर कांग्रेस के ही गले पड़ा

मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव का वही हश्र हुआ जो पहले से तय दिख रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम से विपक्ष के साथ सत्तापक्ष भी परिचित था, लेकिन उसने जिस आनन-फानन अविश्वास प्रस्ताव की मांग मंजूर की उसकी उम्मीद विपक्ष को शायद ही रही हो। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान यह झलका भी कि विपक्षी दल इतनी जल्दी उस पर बहस के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी नेताओं की दलीलें सुनकर देश के लोग शायद ही किसी नतीजे पर पहुंचे हों, क्योंकि उनके पास घिसे-पिटे आरोपों को दोहराने के अलावा और कुछ नहीं था। विपक्ष के आक्रामक, किंतु आधारहीन आरोपों का जवाब सत्तापक्ष और खासकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रभावी तरीके से दिया उससे समझना कठिन है कि विपक्षी दलों को अविश्वास प्रस्ताव से हासिल क्या हुआ? अधिकांश विपक्षी दलों के समर्थन वाला तेलुगु देसम पार्टी की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव मूलतः इस शिकायत पर केंद्रित था कि केंद्र ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? सरकार के जवाब से यह साफ हो गया कि विशेष दर्जे के बहाने आंध्र के लोगों को बरगलाने की राजनीति की जा रही थी और प्रधानमंत्री के आगाह करने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू वाइएसआर कांग्रेस की चाल में जा फंसे थे।

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी सबके केंद्र में थे। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या वह वाकई ऐसा कुछ बोलेंगे जिसका असर भूकंप सरीखा होगा? अफसोस कि वह ऐसा कुछ नहीं बोल सके। उलटे उन्हें अपनी कुछ बातों के लिए शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने भाषण के अंत में भले ही यह कहा हो कि उनके दिल में सबके लिए प्रेम है, लेकिन पूरे भाषण के दौरान उनकी भावभंगिमा आक्रोश और अंहकार से भरे नेता की रही। उनकी ओर से प्रधानमंत्री को जबरन गले लगाना बेहद नाटकीय रहा। पीएम को गले लगाने के बाद राहुल ने अपने सहयोगियों की ओर देखकर जिस तरह आंख मारी उससे गले मिलने के उनके नाटकीय आचरण की पोल ही खुली। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उनके इस व्यवहार की जमकर खबर भी ली। राहुल ने प्रधानमंत्री को यह जो चुनौती दी थी कि वह उनकी आंख में आंख डाल कर बात नहीं कर सकते उस पर भी उन्हें इस करारे तंज का सामना करना पड़ा कि भला एक कामदार व्यक्ति एक नामदार से कैसे आंखें मिला सकता है? प्रधानमंत्री ने राहुल के साथ विपक्षी दलों को भी यह याद दिलाया कि आंख में आंख डालकर बात करने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस ने कैसा व्यवहार किया? इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस किस तरह सरकारों को गिराने का खेल खेलती रही है। उन्होंने राहुल के साथ सोनिया गांधी को भी उनके उस बयान के लिए निशाने पर लिया कि कौन कहता है कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है? राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत में सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोलकर भी मुसीबत ही मोल ली। लगता है कि उन्होंने इसी मसले पर खून की दलाली वाले अपने बयान से कोई सबक नहीं सीखा। कांग्रेस को राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वह पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सरकार के समझ तगड़ी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाते हुए जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति से अपनी बातचीत का हवाला देकर दावा किया कि इस सौदे में गोपनीयता का कोई प्रावधान नहीं है उससे यही जाहिर हुआ कि उन्हें बिना सोचे-विचारे बयान देने की आदत पड़ गई है। राहुल के बयान के दो घंटे के भीतर फ्रांस सरकार ने साफ किया कि इस तरह का कोई प्रावधान न होने की बात सही नहीं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राफेल सौदे को लेकर संप्रग सरकार द्वारा किए गए समझौते का जिक्र कर कांग्रेस अध्यक्ष के दावे को झुठला दिया। प्रधानमंत्री भी यह कहने से नहीं चूके कि एक पारदर्शी रक्षा सौदे पर उलटे-सीधे आरोप लगाना बचकाना व्यवहार है। प्रधानमंत्री ने बैंकों के फंसे कर्जे पर भी विपक्षी दलों को आईना दिखाते हुए जिस तरह अनुत्तरित किया उससे यही लगा कि अविश्वास प्रस्ताव उनके और खासकर कांग्रेस के ही गले पड़ा।

अवधेश राजपूत

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अन्य मामलों के साथ भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। निःसंदेह यह एक गंभीर मसला है, लेकिन यह कानून एवं व्यवस्था से जुड़ा है, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है। विपक्ष यह जानते हुए भी एक अर्से से इस मसले पर मोदी सरकार को घेर रहा है कि कानून एवं व्यवस्था पर केंद्र राज्यों को निर्देश देने तक ही सीमित है। विपक्ष भीड़ की हिंसा के मामलों को लेकर यह कहने की कोशिश करता दिखा कि ये मामले मोदी सरकार के रुख-रवैये के चलते बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर कोई भी सरकार यह क्यों चाहेगी कि उसके शासन में समाज और देश को शर्मिंदा करने वाली घटनाएं घटें। बेहतर होता कि भीड़ की हिंसा पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय इस तरह की वारदातों को रोकने के उपायों पर कोई ठोस और सकारात्मक चर्चा होती ताकि समाज को कोई सही संदेश जाता।

राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को आर्थिक मसलों पर भी कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह रही कि नोटबंदी के दो साल बाद उसे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। नोटबंदी के बाद जीएसटी आए हुए एक साल बीत चुका है और यह एक तथ्य है कि अर्थव्यवस्था को जो झटके लगे थे उससे उबर आया गया है। अब जब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और पांचवां स्थान अर्जित करने की ओर बढ़ रही है तब उसकी खराब हालत का जिक्र करने का औचित्य समझना कठिन था। भले ही अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की हो, लेकिन वह अच्छे से नजर नहीं आई। सत्तापक्ष की ओर से विपक्षी एकता पर जमकर चुटकी ली गई तो इसीलिए कि जहां कई विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं वहीं कुछ खुद को उससे ताकतवर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से यही अधिक प्रकट हुआ कि विपक्ष के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिन पर वह सरकार को घेरकर जनता का ध्यान आकर्षित कर सके। ऐसा लगता है कि वह अपने ही दांव में फंस गया। विपक्षी दलों की ओर से जो मुद्दे उठाए गए उन पर सरकार आसानी के साथ जोरदार पलटवार करने में समर्थ रही।

अभी आम चुनाव में देर है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगर विपक्ष को सरकार के सामने ढंग की चुनौती पेश करनी है तो उसे अपुष्ट आरोप लगाने से आगे बढ़ना होगा। यह अच्छी बात नहीं कि विपक्ष उन मुद्दों को गंभीरता के साथ सामने नहीं ला पा रहा जो आम जनता को कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष इसलिए राजनीतिक गंभीरता का परिचय देने की जरूरत नहीं समझ रहा, क्योंकि वह यह जानता है कि अपने देश में चुनाव भावनात्मक मसलों पर लड़े जाते हैं।

response@jagran.com

आंखों में समाया अविश्वास प्रस्ताव

हास्य-व्यंग्य

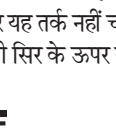

निर्मल गुप्त

आखिरकार सबको पता चला कि गले लगकर, गले पड़कर और आंख मारकर भी राजनीति की जाती है

आखिरकार आधी रात के करीब अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। यही उसकी नियति थी। लाख टके का सवाल यह रहा कि कोई कहीं ऐसे भी गिरता है भला। अरे गिरना ही था तो जरा सलीके से गिर लिए होते। कम से कम सधाए हुए फिल्मी घोड़ों की तरह ही चारों खाने चित हुए होते। जानकार बताते हैं कि एक फिल्म के लिए कुछ घोड़ों को गिरने के लिए इतना सिखाया गया कि वे शूटिंग खत्म होने के बाद जब सरेराह चलते तो बड़े मजे से गिर कर लोटपोट हो जाते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनका सरपट दौड़ना दुर्लभ हो गया। वे तभी विश्वसनीय लगते जब खुलेआम धराशायी होते। कहने वाले कह गए है -

गिरो! तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो/ पर कुछ अलग ढंग से गिरो/ गिरने के भी कई ढंग होते हैं! हर गिरावट के यकीनन कुछ आदाब होते हैं।

क्या आपको पता है कि कभी-कभार कुछ चीजों का गिरना ही ठीक होता है। मसलन थर्मामीटर में तापक्रम नीचे गिरता है तो आदमी भला-चंगा होता है। सेब पेड़ से नीचे टपकता है तो उसके नीचे बैठा अच्छा-भला आदमी देखते ही देखते साइंटिस्ट बन जाता है। बंदा अपने जमीर से गिरता है तो उसके जीवन में सुख सुविधाओं के स्तर को स्वाभाविक रूप से ऊपर उठता है। आसमान से बूंदे गिरती हैं तो प्यासी धरती लहलहा उठती है।

अविश्वास प्रस्ताव गिरने के पहले संसद में दिन भर खूब उठापटक रही। नेता लोग अपने-अपने एजेंडे के क्रम में तमाम तरह के सवालों को उठाते-गिराते रहे। नाटकीय अंदाज में डायलॉग बोलते रहे। वे भी बोले जिनके अपने घर कांच के थे। शायद उनको पता था कि इस बुलेटप्रूफ तकनीक के जमाने में कोई निरीह पत्थर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नेता केवल बोलने के लिए बोले और कुछ ऐसे बोले कि समझ ही नहीं आया कि वे किसके पक्ष में बोल रहे हैं। कुछ ऐसा भी बोले कि सुनने वालों को अगले दिन अखबार का सहारा लेना पड़ा ताकि यह जाना जा सके कि उन्होंने कहा क्या था? कुछ ऐसे भी रहे कि बोलने से रह गए। हालांकि वे जब बोलने की जिद करने लगे तो मन ही मन यह प्रार्थना करनी पड़ी कि अब बस करो भगवन।

हम यह तो जानते थे कि लोकतंत्र तरह-तरह के सियासी भावों से प्रगाढ़ होता है, लेकिन यह नहीं पता था कि गले लगकर, गले पड़कर और आंख मारकर भी राजनीति की जाती है। लगता है कि आंख मारना अब हमारा राष्ट्रीय खेल बनने वाला है। एक षोडशी का 'आंख मारू' प्रकरण जब से वायरल हुआ है तबसे लगता है कि नेता लोग भी यह समझ गए हैं कि जैसी चर्चा और फिर परिचर्चा आंख मारने से होती है वैसी और किसी काम से नहीं। अब समझ आया कि आंखों को लेकर इतने गाने क्यों बने और क्यों वे हिट हुए? मुझे लगता है कि ऐसा कोई गाना बनना चाहिए-एक आंख मारूं तो तेरी सरकार गिर जाए? इसके बाद गीतकारों और संगीतकारों की जोड़ी शायद ऐसे और भी गाने बनाने पर विचार करे। राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर जिस तरह आंख चली उससे यह भी समझ आया कि बात तभी दूर तलक जाती है जब वह नैनों के बांकपन के उड़नखटोले पर सवार होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के एकटक देखने-सुनने वाले एक उद्भट विद्वान का कहना है कि अगले चुनावों में यह कला बड़े गुल खिलाएगी। मुझे लगा कि अगर आंखों का इस्तेमाल इतने काम का हो सकता है तो फिर कमर चलाना तो और भी काम का साबित होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर साहब वर्षों तक कमर मटकाते रहे, लेकिन कुछ न हुआ, लेकिन एक दिन उनका कमर मटकाते हुए वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि वह डब्बू अंकल के रूप में मशहूर हो गए और वह जिन असली शख्सियतों की नकल उतारा करते थे आज वही उनके मुरीद बन गए हैं।

अविश्वास प्रस्ताव पर तमाम नेताओं के विचार सुनने के बाद आपके विचार चाहे जैसे रहे हों, मुझे तो उसने लेट नाइट मूवी जैसा आनंद प्रदान किया। इसके बावजूद किया कि अविश्वास प्रस्ताव का क्लाइमेक्स पहले से पता था। अच्छी बात यह रही कि कोई ब्रेक भी नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद होने वाला विश्वास सामने था, फिर भी उत्सुकता यह कि संसद में उसके दर्शन करके ही सोया जाए। ऐसे असमंजस भरे समय में जब विश्वास और अविश्वास एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हों तब किसी को कैसे ढंग से नींद आए? संशय के गहरे अंधेरे में आमतौर पर निद्रा तो आसपास नहीं फटकती अलबत्ता रतजगा जरूर होता रहता है। शुक्र है कि बातें रात के पार नहीं गईं। यह बात और है कि अगले दिन कुछ लोग इस पर अफसोस जताते मिले कि आखिर वह सब देखने-सुनने के लिए रात काली करने की क्या जरूरत थी जिसे पहले भी कई बार देख-सुन चुके हैं? ऐसे लोगों के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि वे आनंद की खोज करना नहीं जानते।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

डाटा लीक से अनुमानित क्षति

(नुकसान करोड़ रुपये में)

स्रोत : आइबीएम

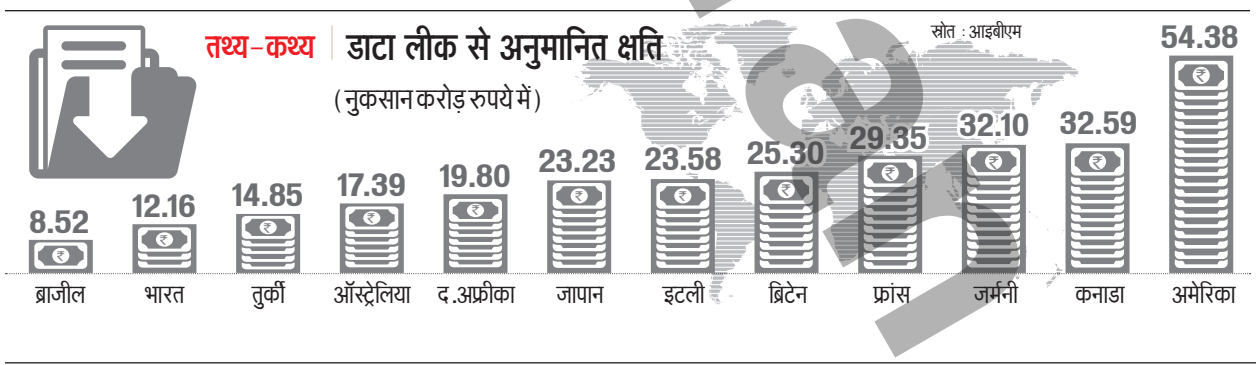

ऊर्जा

आत्मज्ञान

आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मानव शरीर नश्वर है, किंतु मानव जीवन देव-दुर्लभ है। भगवान ने मानव को जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रदान किया है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि विद्या से अमृत-तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या का मुख्य फल विमुक्ति कहा गया है। विमुक्ति दो अर्थों में प्रयुक्त है, प्रथम अज्ञान से विमुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति अर्थात अंधकार का समाप्त होना और प्रकाश का उदीयमान होना। द्वितीय इस संसार से विमुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति या परम तत्व का साक्षात्कार और भगवत्प्रेम। इसलिए हम अपनी आत्मा अर्थात आत्म का ज्ञान करें। काम, लोभ, मोह, क्रोध, राग एवं द्वेष रूपी कामनाओं एवं वासनाओं की लहरें मानव शरीर को उद्वेलित करती रहती हैं और तब हम आत्मज्ञान के माध्यम से अपने इन्द्रिय विचलन को रोकते हैं।

ज्ञान अर्थात ब्रह्मज्योति का स्फुरण विद्या से प्राप्त होता है। इस ब्रह्मज्योति का साधन विद्या ही है। इंद्रिय संयम के अभाव में मन चंचल हो जाता है। जैसे ही हम इंद्रिय संयम से कामनाओं एवं वासनाओं को शांत कर लेते हैं, वैसे ही हमें हमारे आत्मस्वरूप का दर्शन होने लगता है। हमें यह अनुभव होने लगता है कि जीवात्मा ब्रह्मज्योति से स्वयं ज्योतिर्मय है। जीवात्मा परमानंद और ब्रह्मानंद की असीम अनुभूति करने लगता है तथा ऐसी अवस्था में मानव में उसके अंतस से अज्ञान अभाव और आसक्ति सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाती है। कामना, वासना और तृष्णा स्वमेव तिरोहित हो जाती है और अज्ञान जनित दुखों से मुक्ति मिल जाती है।

महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में इस संदर्भ में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होते ही द्रष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीव की यह स्थिति दिव्य होती है, जब उसे अपने आत्मस्वरूप चैतन्य का ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हर्ष-विषाद नहीं रह जाते। ऐसे पुरुष वाद-विवाद को त्यागकर स्थिर हो जाते है। संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है कि कोई कितने भी कर्म कर ले, कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले अथवा कितने भी देवताओं का भजन कर ले, जब तक आत्मा-परमात्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ ही हो जाता है। सच यह है कि ज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप है आत्मज्ञान।

डॉ. रामहर्ष गुप्त

हिस्से की लड़ाई

केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद भाजपा का विजय रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। इस रथ पर सवार होकर पार्टी ने एक के बाद कई राज्य फतह कर लिए। यहां तक कि जिन राज्यों की सियासत में भाजपा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर आगे बढ़ी थी वहां भी उसने उन वरिष्ठ साथियों को कनिष्ठ भूमिका में पहुंचा दिया है। इस दौरान पार्टी में नए-नए चेहरे भी स्टार बन गए, लेकिन केंद्रीय संगठन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हर बार नेताओं में यह आशा जगती है कि शायद अबकी उनका सितारा चमकेगा, लेकिन..। ऐसे में त्रिपुरा की जीत के लिए खुद को स्टार मान रहे एक नेता ने उत्साहित होकर एक अन्य नेता की हिस्सेदारी में दखल देने की कोशिश की। उक्त नेता ने एक खास अवसर पर ट्वीट कर ओडिशा की जनता को शुभकामना दे दी। अब जो नेता ओडिशा की जिम्मेदारी देख रहे हैं उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने तत्काल फोन लगाकर शुभकामना वाले ट्वीट की मंशा पूछ ली और परोक्ष रूप से आगाह भी कर दिया कि भविष्य मे ऐसा न करें। बताते हैं कि तब से उक्त महोदय यह आशा लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उनके जिम्मे फिर कोई राज्य दिया जाएगा। अब देखते है कि उनकी यह आस कब पूरी होती है या फिर उन्हें मायूस ही रहना पड़ेगा।

राजरंग

गवर्नर की उम्र

क्या मेरी उम्र गवर्नर बनने की है? पार्टी के साथ काम करने और लोगों की सेवा करने का समय है भाई। नेताजी थोड़ा गुस्से में सोशल मीडिया पर बरस रहे थे। अफवाह उड़ाने वाला यह माध्यम कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं? इस सवाल पर वह बेधड़क बोल उठे। वही कुछ पुराने लोग जिन्हें थोड़ा बहुत इधर उधर सरका दिया गया तो बिदके हुए हैं। सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय सोशल मीडिया के सहारे मुझे ही गवर्नर बनाकर नार्थ ईस्ट के राज्यों में भेजने का शिगूफा छोड़ रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। समय के साथ लाइन पर आ जाएंगे। उत्तर भारत के एक बड़े राज्य के मुखिया ने अपनी भड़ास कुछ यूं निकाली।

संस्कृत पर बिदके

संसद में 22 भाषाओं में बोलने की सुविधा से गदगद माननीय पिछले दिनों संस्कृत शब्दों के प्रयोग के सुझाव पर बिदक गए। हुआ यह कि जब राज्यसभा में सभापति इन सुविधाओं का एलान कर रहे थे, उसी समय अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले स्वामी जी ने संस्कृत को इन सभी भाषाओं की जननी बताते हुए कहा कि इन भाषाओं के साथ संस्कृत शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो अधिक बेहतर होगा। फिर क्या सुविधाओं से गदगद दिखने और उसे लेकर मेज थपथपाने वाले माननीयों ने हो-हल्ला शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सभापति ने इसे निजी राय बताते हुए मामले को शांत किया। पर सदन के भीतर इसे लेकर एक चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि आखिर संस्कृत से इन माननीयों को इतना परहेज क्यों? इसमें भी उन्हें राजनीति दिखाई देती है?

असली किसान

किसानों के मुद्दों की बात जब आती है तो हर नेता से लेकर विशेषज्ञ सब किसान बन जाते हैं। लेकिन लुटियंस जोन में खेती के एक विशेषज्ञ ऐसे हैं जो वास्तव में ही किसान हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद न सिर्फ कृषि के विशेषज्ञ हैं, बल्कि खुद किसान भी हैं। मक्का से लेकर गेहूं तक की खेती वह करते हैं। हाल में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने खेतों के बीच खड़े चंद की फोटो जब सोशल मीडिया पर डाली तो उसे वायरल होते देर न लगी। वैसे बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की दोगुनी आय करने का जो लक्ष्य रखा है, उसकी रणनीति बनाने में चंद ने अहम भूमिका भी निभायी है। बहरहाल किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा। उनके खेत में फसल जरूर लहलहा रही है।

ट्वीट-ट्वीट

राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या के बाद गो-रक्षा के नाम पर दूसरा भयावह कत्ल। अब 50 साल के अकबर खान की गो-तस्करी के शक में पीट-पीट कर निर्मम हत्या। फर्जी गो-रक्षा के नाम पर यह आतंक कितनों की जान लेगा? ये तो न पीएम मोदी की मान रहे न सुप्रीम कोर्ट की!

समीर अब्बास@TheSamirAbbas

अविश्वास प्रस्ताव के मसले पर शिवसेना ने यही सबक सीखे होंगे कि राजग उनके बिना भी आगे बढ़ सकता है और भाजपा के बिना वह शून्य है।

मोहन सिन्हा@Mohansinha

मैं जानता हूं कि लोग इस तथ्य को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार पर निशाना साधने के लिए किसी विपक्षी नेता ने अपने आवंटित समय का सही उपयोग किया तो वह असदुद्दीन ओवैसी रहे। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ सरकार को आड़े हाथों लिया।

यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

वर्ष 2008 में संप्रग के दौर से ही सरकारी बैंकों के एनपीए की जड़ें तलाशने को लेकर पीएम एकदम सही हैं। वह 'फोन बैंकिंग' को लेकर भी दुरुस्त हैं, लेकिन उन्हें कर्ज लेने वालों, उनके खातों और रकम के तारीख सहित आंकड़े भी सार्वजनिक करने चाहिए ताकि लोगों को भी इसका पता चल सके।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

जनपथ

झप्पीबाजी ठीक थी किंतु मारकर आंख,
किया-कराया कर दिया राहुल जी ने राख।
राहुल जी ने राख यही तो है नादानी,
जिसके कारण रोज पड़ रही मुंह की खानी।
बनो जरा गंभीर देश तब होगा राजी,
सत्ता में लौटाय न सकती झप्पीबाजी।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 29 अंक 5**